

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday December 11, 1972/Agra
hasyana 20, .894 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock

[Mr. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों और ग्रामीण जन-
संख्या के बीच अनुपात

+

*382. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री मूल चन्द्र बाग्य :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन
मंत्री यह कताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों
में डाक्टरों और ग्रामीण जनसंख्या के बीच
क्या अनुपात है ;

(ख) ऐसे ग्रामों की संख्या कितनी है
जहाँ कोई भी डाक्टर नहीं है ;

(ग) क्या देश में लगभग 20 हजार
डाक्टर बेरोजगार हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या
प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही
की गयी है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और
परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमरासकर
वीरवार) : (क) व्यावहारिक जनकर्मित
अनुसंधान संस्थान द्वारा 1966 में किये गये
एक अध्ययन के आधार पर यह अनुमान

लगाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय
डाक्टरों और जनसंख्या का अनुपात लगभग
1 और 11,000 है ।

(ख) विभिन्न ग्रामों में कितने डाक्टर
आधुनिक चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस कर
रहे हैं उसके संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं
है । वैसे, 30 जून, 1972 की स्थिति
के अनुसार 140 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
बिना डाक्टरों के थे ।

(ग) 1970 तथा 1971 में क्रमशः
2497 और 3953 डाक्टरों के मात्र रोजगार
कार्यालयों के रजिस्ट्रारों में दर्ज थे ।

(घ) ग्रामतौर पर डाक्टर ग्रामीण
क्षेत्रों में काम करना नहीं चाहते । फिर भी,
केन्द्रीय और राज्य सरकारों डाक्टरों को उन
क्षेत्रों में काम करने के लिये प्रोत्साहन देने
के संबंध में भरसक प्रयत्न कर रही है ।
इस संबंध में एक विवरण सभा-पटल पर
रख दिया गया है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार राज्यों को शत प्रतिशत
सहायता देती है जिससे राज्य सरकारें
सुदूरपूर्वी, पिछड़े हुए और दुर्गम सभ्य
जाने वाले 400 निविष्ट क्षेत्रों में काम करने
वाले डाक्टरों को प्रति मास 150 रुपये का
भत्ता दे सकें ।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें
डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने
के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही हैं :

(1) ग्राम एवं माहुरी क्षेत्रों में काम
करने वाले डाक्टरों का एक ही
संबंध बनाना ।

- (2) ग्राम-भरता, परिवहन सुविधायें, बिना किराये के सुसज्जित मकान, साफ पानी, बिजली आदि सम्बंध प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करना ।
- (3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में खासकर भवनो, रिहायशी क्वार्टरों आदि की सुविधाओं में सुधार करना ।
- (4) ग्राम क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक सेवा-निवृत्त डाक्टरों को पुन नियुक्त करना ।
- (5) ग्रामों में बेतनवृद्धिया देना ।
- (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काफी मात्रा में दवाइयों तथा उपस्कर की व्यवस्था करना । कुछ राज्यों में चिकित्सा छात्रों को कुछ वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम करने को प्रोत्साहन देने के लिये छात्रवृत्तियों/वजीफों की प्रवृत्ति को भी ।
- (7) विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के उपलब्ध चिकित्सकों की ग्रामीण सेवाओं का ग्राम क्षेत्रों में उपयोग करके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्री मंत्री महोदय ने कहा कि भागलपुर पर डाक्टर कर्मियों के काम करना नहीं चाहते । जो विचारण उन्होंने समा-मंडल पर रखा है, उससे तो यह स्पष्ट है कि उन्हें गांवों में जाने के लिये काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है किंतु भी वे गांवों में नहीं जाना चाहते क्या इसका कारण यह है कि वैदिक शिक्षा पद्धति ऐसी है इसकी खोजी है, उसमें इसकी समझ-बूझ है कि एक बार जो विद्यार्थी उसमें से निकल जाता है, वह

गांवों की तरफ मुंह ही नहीं करता ? यदि यह सच है तो वैदिक शिक्षा पद्धति में कोई आर्थिक परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ? उदाहरण के लिये क्या एल० एम० पी० कोर्स को फिर से शुरू करने के बारे में किसी स्तर पर चर्चा हुई है ?

श्री उलासकर बीक्षित भामूल परिवर्तन का विचार तो नहीं है । हमारे मतानुसार भामूल परिवर्तन शक्य भी नहीं है । एल० एम० पी० परीक्षा का भ्रम पुनः-उजीवन किया जाय, तो भी शिक्षा पद्धति श्रीमन् आधुनिक ही रहेगी । मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में प्रशिक्षित चिकित्सक का रहन-सहन, विचार और मस्कृति तथा मनोवृत्ति बहुत बदल जाती है और इस कारण गांव जैसी स्थिति में जाकर काम कर सकना, चिकित्सा का कार्य करना, उनको कठिन लगता है । यदि हम उस पद्धति को अर्वाचीन पद्धति को रखेंगे तो उसमें कोई ऐसा परिवर्तन हमें शक्य नहीं लगता है कि जिससे वे ऐसे गांवों में जा कर स्थायी रूप से काम कर सकें, जहापर सामान्य, सांस्कृतिक या मध्य जीवन की सुविधायें सर्वथा अप्राप्य है ।

लेकिन, श्रीमन्, इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये इस समय दो प्रकार के विचार चल रहे हैं—पहला यह कि जो हमारी प्राचीन भारतीय पद्धति है, में प्रशिक्षित हैं, उनको तैयार करके जहा कही है, वहा पूरा करें या जितना पूरा कर सके उतना पूरा करे । दूसरा विचार यह चल रहा है—श्रीमिनिस्ट्री ने निश्चय नहीं किया है, विचाराधीन है—कि कोई कम समय का कोर्स लें तो हम अधिक जगहों पर पहुंच सकेंगे और जसके वर्तमान परिस्थिति में सुधार हो सकेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सरकार ने इस चुनाव पर विचार किया है कि विद्यार्थी जो

डाक्टर बनकर निकलते हैं उनके लिये यह अनिवार्य कर दिया जाय कि वे दो माल तक गांव में रहकर चिकित्सा करेंगे तभी उनको डिग्री दी जायेगी, उसमें पहले नहीं ?

श्री उमाशंकर बीक्षित : इस तरह का निश्चय सभी राज्य सरकारों ने किया है—कहीं नहीं हुआ हो, तो मुझे इस समय सूचना नहीं है, स्मरण नहीं है—लेकिन अधिकांश जगहों पर बाण्ड लिखाया जाता है । चूकि इसमें कुछ कानूनी पेचीदगी थी और यह समझा गया कि कठिनाई होगी, इसलिये भारत सरकार ने यह नियम बनाया है कि उनसे 2 वर्ष का बाण्ड लिखवा लेते हैं और जब 5 वर्ष के बाद वे परीक्षा पास कर के निकलेंगे तब उनको अवश्य दो वर्ष गांव में काम करना पड़ेगा । प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में मैं तत्काल तो नहीं कह सकता, लेकिन माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको लिख कर सूचित कर दूंगा ।

श्री मूल चन्द्र ढागा : रूपा कर बतलाइये—आज केन्द्रीय सरकार कितना रपया भत्ते के रूप में डाक्टरों को देती है और किस-किस राज्य को कितना-कितना देती है ?

श्री उमाशंकर बीक्षित : अलग-अलग भत्ते की सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री मूल चन्द्र ढागा : आपने यह बतलाया है कि केन्द्रीय सरकार भत्ता देती है, क्या आप अलग-अलग नहीं बता सकते कि कुल कितना भत्ता आज तक केन्द्रीय सरकार को दिया जाता रहा है ?

श्री उमाशंकर बीक्षित : भत्ते का संबंध बहुत व्यापक है । आप लिखकर सोचेंगे तो मैं बतलाऊंगा कि कौन-कौन सा भत्ता दिया जाता है

अध्यक्ष महोदय : भत्ता कहां पूछा है ?

श्री मूल चन्द्र ढागा : जो गांव में जाते हैं उनको केन्द्रीय सरकार भत्ता देने के लिये तैयार है । मैं पूछ रहा हूं कि कितना वे चूके हैं और कितना इस साल में देंगे ?

श्री उमाशंकर बीक्षित : जो डी क्लास के स्टेशन हैं, उनके बारे में 150 रुपये मासिक का विशेष भत्ता देने का निश्चय किया गया है और जो डाक्टर बहा गये हैं उनको दिया गया है । यदि आप संख्या और राज्यों का नाम चाहते हैं तो तुरन्त नहीं बतला सकूंगा, यदि बाद को पूछेंगे तो अवश्य सूचित कर दूंगा ।

डा० गोविन्द दास रिछारिया : आपने जो अनुपात बतलाया है—क्या जो घनी आबादी के प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, उनमें और बाकी देश में एक सा है, या तो पहाड़ी प्रदेश हैं—हिमालय पर्वत का क्षेत्र, बुन्देलखण्ड का क्षेत्र, उसमें और बाकी देश में एक सा है ?

दूसरी बात यह है कि डाक्टर इसलिए नहीं जाते हैं देहातों में क्योंकि उनको आप और प्रान्तीय सरकारें कम तनखाहे देती हैं इसलिए क्या आप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उनको इतना घन दिया जाये जिससे वे ग्रामीण अस्पतालों में सुविधाजनक रह सकें और जा सकें ?

श्री उमाशंकर बीक्षित : एक जैसा अनुपात नहीं है । जिनको हम अधिक विकसित प्रदेश कहते हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आदि वहां पर डाक्टरों का अनुपात अधिक है और जैसा कि आपने बताया, बुन्देलखंड, हिल एरियाज आदि वहां पर कम है । जहां तक आपने उनके वेतनक्रम की बात कही उसमें कमी नहीं है जो हमारी आल इण्डिया सर्विस प्राइवरी हेल्थ सेक्टरों के लिए है उसमें सभी भत्ते और वेतन मिलाकर लगभग साढ़े 6 सौ, सात सौ से प्रारम्भ होता है, जॉकि पर्याप्त है ।

SHRI S. M. BANERJEE: I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that in the absence of hospitals or dispensaries in the rural areas the Government propose to have mobile dispensaries with qualified doctors so that medical benefits can be had by the village population also.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: This is an excellent suggestion. I have myself had this matter examined, at not a very serious level. It has not yet gone to the Ministry of Finance, Planning Commission, etc. It is an excellent suggestion. But there are aspects which will require very careful consideration particularly in regard to the use of vehicles and their maintenance, repairs, etc.

Proposal to build New Shipyards Establishment of Central Design and Research Centre for Ship Building and Foreign Collaboration

+

*383. SHRI P. M. MEHTA:
SHRI P. GANGADEB:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government of India are going to build two new shipyards and establish a Central Design and Research Centre for ship-building;

(b) if so, where the new shipyards are expected to be located;

(c) whether ship builders in Britain and West Germany were interested in India's proposals for collaboration arrangements to build two new shipyards; and

(d) if so, the nature and extent of the help these two countries would give?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI OM MEHTA):

(a) The question of setting up more shipyards in the country is under consideration. It is also proposed to set up a Central Marine Design and Research Organisation.

(b) The location of new shipyards has yet to be decided.

(c) and (d). Yes, Sir. Possibilities of collaboration are being explored.

SHRI P. M. MEHTA: I would like to know from the hon. Minister whether, taking into consideration the natural advantages of the sea-coast of Saurashtra and the facilities of good harbours of Saurashtra, any proposal is under consideration to set up one Shipyard in Saurashtra region of Gujarat and; if so, the proposed location of the new Shipyard and; if not, the reasons thereof.

SHRI OM MEHTA: The Gujarat Government has recommended Porbunder as the site for the new Shipyard. But I cannot say anything at this stage because all the proposals which have been received from various State Governments are under consideration. The decision will be taken only in the Fifth Plan. Nothing can be said at this stage.

SHRI P. GANGADEB: I would like to ask the hon. Minister whether the Government has made any study of the designs, technical and managerial capabilities to build bigger ships in India and; if so, what are the broad details thereof.

SHRI OM MEHTA: No comprehensive study has yet been made. But we are going to set up a Design Centre for this and already Poland has agreed to give us some help in this direction. The talks are still going on. After that, we will know where we stand. At present, we are purchasing the know-how from foreign countries.

SHRI P. R. SHENOY: I would like to know from the hon. Minister whether the possibility of putting up a